निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर आयोग की जनसुनवाई

करनाल (जेके शर्मा) शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हरियाणा आयोग ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय के सभागार में जन सुनवाई की। इसमें करनाल मंडल के अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों करनाल, पानीपत तथा कैथल से पिछडा वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनो के समूहों में काफी संख्या में आए और अपने सुझाव देकर करीब 25 ज्ञापन सौंपें।

इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष दर्शन सिंह ने कहा कि आप के पास सुझाव लेने तथा विचार जानने के लिए आए हैं कि शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को किस अनुपात में आरक्षण दिया जाए। उन्होने स्पष्ट किया कि आयोग के लिए आप लोगों के विचार बहुत ही मुल्यवान है, उसी के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेके सरकार को सौंप देगा। उन्होंने कहा कि आप अपने उपयोगी सुझाव दें और यदि कोई डाटा हो तो वह भी आयोग को उपलब्ध करवाएं जो सिफारिशें देने में आयोग के लिए बड़ा मददगार होगा।

आयोग ने करनाल में जन सुनवाई से पूर्व फरीदाबाद व गुरूग्राम मण्डल में लोगों के सुझाव स्वीकार किए। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्याम लाल जांगड़ा ने बताया कि आयोग द्वारा 13 फरवरी से 20 फरवरी के बीच मंडल मुख्यालयों पर पब्लिक हियरिंग करके आम जनता से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। इस जन सुनवाई का उद्देश्य यही है कि शहरी स्थानीय निकायों में किस अनुपात में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके बारे में आम जनता से सुझाव प्राप्त किए जाएं। सुझाव मिलने के बाद यह आयोग राज्य सरकार को इस विषय पर अपनी सिफारिशें भेजेगा।

जन सुनवाई के दौरान हरियाणा कश्यप राजपूत महासभा, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा, गौस्वामी समाज, प्रजापति, कुम्हार महासभा, पांचाल महासभा, सैन समाज की सभा सहित अधिकतर प्रतिनिधियों ने आबादी के हिसाब से पिछड़ा वर्ग के लिए शहरी स्थानीय निकायों की संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान की मांग की। इसके अतिरिक्त जातिगत जनगणना व क्रीमीलेयर पर भी सोचे जाने की बात रखी, जिस पर आयोग ने भरोसा दिलाया कि आप द्वारा रखी गई इन मांगों की समीक्षा करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट सिफारिश सहित सरकार को भेजी जाएगी।

युवा कांग्रेस का घंटी बजाओ-सरकार जगाओ प्रदर्शन

करनाल। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय में घंटी बजाओ सरकार जगाओ प्रदर्शन किया। परिवार पहचान पत्र, बीपीएल और वृद्धा पेंशन को लेकर सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।

इस मौके पर दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे लोग अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी में गड़बड़ी होने के कारण आज लोगों को दफ्तरों और अफसरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं फैमिली आईडी में गड़बड़ी होने के कारण लोगों के बीपीएल कार्ड भी कट गए हैं, जिससे गरीबों को मिलने वाला राशन भी बंद हो गया है। जो सर्वे करवाया गया है उससे अब जनता को काफी परेशानियां हो रही हैं। परिवार पहचान पत्र न होकर परिवार परेशान पत्र बन चुका है।

दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि सरकार जल्द फैमिली आईडी को ठीक करवाएं अन्यथा आने वाले विधानसभा सत्र में शिकायतों को दोबारा रखा जाएगा। युवा कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार गरीबी हटाने के बजाए गरीबों को मिटाने का काम कर रही है। देश-प्रदेश की जनता को कागजों में उलझा दिया गया है। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से युवाओं का ध्यान भटकाया जा रहा है। मोदी और मनोहर सरकार के रोजगार देने के दावे खोखले साबित हुए हैं। भाजपा सरकार को पूंजीपति दोस्तों से फुर्सत नहीं मिल रही, इसलिए गरीबों की समस्याओं का हल नहीं कर रही।

सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी से बढ़ा विवाद पड़ा मंहगा

करनाल (जेके शर्मा) सोशल मीडिया पर कमेंट करना कितना खत्तरनाक रूप धारण कर लेता है। इसका उदारण करनाल में उस समय देखने को मिला जब 15-20 लडक़ों ने हथियारों के साथ दूसरे गुट के युवकों पर हमला बोल दिया। हमले के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि युवकों के बीच सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कमेंट करने से चैलेंजबाजी हुई थी। इसके चलते रात को सोशल मीडिया पर ही एक गुट ने दूसरे गुट को करनाल में आकर मिलने का चैलेंज दिया। जैसे ही दूसरा गुट करनाल के सुपर मॉल के पास पहुंचा तो वहां पर 15-20 लडक़ों ने हथियारों से उन पर हमला बोल दिया। हमले में किसी युवक का हाथ कटा है तो किसी का कान कट गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, डीटीपी पर लगाए आरोप

करनाल (जेके शर्मा) करनाल में आईटीआई चौक पर प्रशासनिक अमले द्वारा ग्रीन बेल्ट में अवैध कब्जे करने वालों के निर्माण पर बुलडोजर चलाया तो हंगामा हो गया। स्थिति बिगडने की सम्भावना को देखते हुए पुलिस का बंदोबस्त किया गया था,पर प्रॉपर्टी मालिकों ने डीटीपी पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप लगाकर उन्हें कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दी।

डीटीपी गुंजन तोडफ़ोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए दो जेसीबी मशीने साथ लेकर आईटीआई चौक पर पहुंची। वहां प्रॉपर्टी में बनाई गई कच्ची सडक़ें को ध्वस्त कर दिया गया। एक प्लॉट पर भी कार्रवाई की गई है। यह प्लॉट ग्रीन बेल्ट में बताया जा रहा था। प्लॉट में निर्माण पर तोडफ़ोड़ होने से प्लॉट मालिक भडक़ गया और उसने डीपीटी को कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दे दी।

प्रॉपर्टी मालिक ने कहा कि वे अपनी प्रॉपर्टी के कागजातों को लेकर डीटीपी से मिले थे। उस समय डीटीपी ने कागजातों से संतुष्टि जाहिर की थी और कहा था कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद ही अपनी 500 गज की जमीन पर चारदीवारी करके कब्जा ले लिया था। आज डीटीपी ने उनकी प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चला दिया। प्रॉपर्टी मालिक ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहां पर बिना नक्शे पास बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उन पर तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमेटी टैक्स ले रही है गलियां बनी हुई हैं।

इस बारे में डीटीपी गुंजन ने कहा कि ग्रीन बेल्ट एरिया में कार्रवाई की है। सभी रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही निर्माण तोड़ा गया व नियमों के तहत ही कार्रवाई की गई है।

पूर्व सैनिक 20 फरवरी को दिल्ली में हकों की उठाएंगे आवाज

करनाल। मांगों को लेकर पूर्व सैनिक सभा की मीटिंग 15 फरवरी को जयसिंहपुरा में प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सिंह फौजी की अध्यक्षता में हुई। पूर्व सैनिकों ने कहा कि वे 20 फरवरी को जंतर-मंतर दिल्ली में होने वाले आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण फौजी ने कहा कि पूर्व सैनिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और आर्थिक सौतेलापन के खिलाफ लामबंद हों। सभी ऑनरेरी सभी भूतपूर्व सैनिक ईएसएम आंदोलन का हिस्सा बनकर, अपनी एकता का परिचय दें।

उन्होंने कहा कि भारत के सभी पूर्व सैनिक आर्मी, एयर फोर्स, नेवी से रिटायर्ड अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब वे चुप नहीं बैठेंगे। सरकार को चाहिए वे पूर्व सैनिकों की सभी मांगों को जल्द पूरा करे अन्यथा सरकार को बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। आगामी 20 फरवरी को वे हक की लड़ाई के लिए ओआरओपी-टू के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन में भारतीय सेना के जवान, जे.सी.ओ. के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके पीछे रिटायर अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। ओआरओपी-टू में भारतीय सेना, एयरफोर्स एवं नेवी डिफेंस, तीनों अंग के रिटायर पीएमआर वाले को इससे वंचित कर दिया गया है, ऑनरेरी कमीशन का पेंशन कम कर दिया। ये पूर्व सैनिकों के साथ सरासर नाइंसाफी है। फौजी ने कहा कि अधिकारी चाहते ही यही हैं कि कोई भी सैनिक संगठन ओआरओपी-2 के खिलाफ आवाज ना उठाए लेकिन अब पूर्व सैनिक जोर शोर से अपनी आवाज उठाएंगे वे चुप नहीं बैठेंगे।

पूर्व सैनिकों को एक सुर से दिल्ली जंतर मंतर पर प्रस्तावित 20 फरवरी से होने वाले आंदोलन में बढ़ चढक़र हिस्सा लेना चाहिए।

इस अवसर पर कैप्टन जागे सिंह, कैप्टन तारा चंद, सुबेदार इंद्र सिंह, सुबेदार धर्मपाल सिंह, सुबेदार रामस्वरूप पूनिया, सुबेदार अनुप मान, सुबेदार धर्मपाल, नायक सुरेश कुमार, नायक कृष्ण कुमार व नायक बाबू राम सहित अन्य मौजूद रहे।